



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका

सरिता बाजिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र

राजकीय कन्या महाविद्यालय, बबाई, (नीमकाथाना), राजस्थान

शोध सार

प्राचीन काल से ही कृषि भारतीय अर्थव्यवाला का प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्रधान व्यवासाय होने के कारण कृषि भारत जैसे विकासशील देश की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा बीत रोजगार एवं जीवन यापन का एवं विदेशी प्रमुख साबन औद्योगिक विकास, वाणिज्य व्यापार का प्रमुख आधार है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ तथा विकास की कुन्जी कहा जाता है। कृषि से अभिप्राय उन सभी क्रियाकों से है जिनका संबंध फसलों के उत्पादन के लिए भूमि को जोतने से है। कृषि भारत के आर्थिक विकास का इंजन है और इससे सर्वाधिक लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देने, किसानों की आय में वृद्धि करने और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

मूल शब्द – कृषि, रासायनिक, जनसंख्या, आय, उर्वरक, रोजगार।

भारतीय कृषि की प्रकृति

स्वतंत्रता के समय कृषि परम्परागत तरीके से की जाती थी। उस समय न तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता था और न ही उन्नत बीज थे। कृषि मुख्य तौर पर जीवनयापन के लिए होती थी न कि वाणिज्यिक स्तर पर। इसका अनुमान इस बात से वर्ष 1951–52 लगाया जा इसका अनुमान सकता है कि मैं किसानों के उपयोग में लगभग 45 प्रतिशत अंश उनके ही द्वारा उत्पादित वस्तुओं का होता था।

वर्तमान परिदृश्य में कृषि में सकल मूल्य वृद्धि वर्ष 2014–15 में 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक से वर्ष 2016–17 में 6.3 प्रतिशत धनात्मक रही, जो कि वर्ष 2018–19 में फिर 2.9 प्रतिशत तक रही। वर्ष 2022–23 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.11 प्रतिशत रहा है।

भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएँ

भारत की मौलिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में कृषि की कुछ मौलिक विशेषताएँ निहित हैं, जो निम्न प्रकार हैं –

खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता –

भारत में कृषि योग्य भूमि पर जितनी फसले उगाई जाती है। उनमें लगभग 25 प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलों तथा 25 प्रतिशत भाग पर व्यापारिक फसलों की खेती की जाती है।

मिश्रित खेती

भारतीय कृषि में मिश्रित कृषि देखी जाती है। इसमें किसान एक ही खेत में एक से अधिक फसलों की बुआई करता है।

फसलों में विविधता

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु तथा मिट्टी में विविधता पाए जाने के कारण भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसले उगाई जाती है। ऋतुओं के अन्तर्गत देश में तीन प्रमुख फसलें पाई जाती हैं; जैसे खरीफ, रबी जायद।

कृषि जोतों का छोटा होना

जनसंख्या की दृष्टि के कारण भूमि का बंटवारा होने या उत्तराधिकार के नियमों का परिवार में पाए जाने के कारण कृषि जोत की भूमि छोटी हो जाती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को कई बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं—

कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिस कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, वन तथा अन्य प्राथमिक क्रियाओं का बहुत योगदान रहा। 2020–21 में सकल मूल्य वर्धन में कृषि व सहायक क्रियाओं का भंश 21.8 प्रतिशत रहा था तथा 2022–23 में यह 18.11 प्रतिशत रहा इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान धीरे-धीरे कम हुमा वर्हीं उत्पादन की दृष्टि से इसका योगदान बढ़ा है।

कृषि का रोजगार की दृष्टि से महत्व

देश की लगभग दो-तिहाई आबादी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में संलग्न है। इसको निजि क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। सन् 1950 में कुल जनसंख्या का लगलग 70 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था, जो सन् 2019 में कम होकर 53 प्रतिशत हो गया।

भारतीय कृषि का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मोगदान विदेशी व्यापार की उष्टि से भी कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है विगत कुछ वर्षों में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात की मात्रा व मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है। 2010–11 में कृषिगत व सहायक पदार्थों का अंश 9.7 प्रतिशत था जो 2020–21 में 14.3. प्रतिशत हो गया।

खाद्यान्न व चारे की पूर्ति में योगदान

भारत में कृषि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देश की विशाल, एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त देश के पशुधन को चारा है। कृषि से ही प्राप्त होता उद्योगों के लिए कच्चे माल योगदान —कृषि देश के की नापूर्ति में अनेक छोटे छोटे उद्योगों का आधार है भी है। सूती वस्त्र, चीनी पटसन, चाय, कॉफी, खड्डा वनस्पति धी, तेल मादि अनेक उद्योग अपने कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से देश की कृषि पर ही निर्भर हो लघु उद्योगों में, चावल, आटा, तेल व दाले आदि की मिलों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है।

कृषि का निर्धनता उन्मूलन में योगदान —

भारत में कृषिगत उत्पादन के बढ़ने का प्रभाव गरीबी को कम करने के रूप में देखा गया है। गरीबी का विचार केलोरी से जुड़ा है। अतः खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने से ही इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धि बढ़ायी जा सकती है, जिससे गरीबी कम होती है।

परिवहन के साधनों की आय का स्रोत

देश में कृषि उत्पादन के संबंध में भारी प्रादेशिक — अन्तरों के कारण रेल, मोटर मादि परिवहन के साधनों की शमाय का काफी बड़ा भाग कृषि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से प्राप्त होता है।

सामान्य जीवन स्तर में सुधार व मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने में योगदान

सामान्य जीवन स्तर में सुधार व मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कृषिगत विकास आवश्यक भारत में विकास की कुंजी कृषि के हाथ में मानी गयी है। खाधानों, फल—सब्जी व तिलहन, गन्ना भादि की पैदावार बढ़ाकर ही आम आदमी का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

देश का सरकारी बजट कृषि क्षेत्र से महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होता है। देश में कराधान, ऋण तथा व्यय संबंधी नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कृषि उत्पादन की मात्रा के आधार पर किया जाता है। देश में प्रति वर्ष कृषि विकास पर भारी मात्रा में धन व्यय किया जाता है तथा देश को प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की आय मालगुजारी तथा कृषि आय कर से प्राप्त होती है।

भारतीय कृषि की समस्याएँ—

भारत में वर्ष के क्षेत्र में न केवल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम पाई गई, बल्कि प्रति श्रमिक उत्पादकता भी कम पाई गई। इसके पिछड़े होने या उत्पादकता के निम्न होने अथवा कृषि के असन्तोषजनक विकास के लिए सामूहिक रूप से अनेक कारक उत्तरदायी रहे हैं। इनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार हैं—

मानवीय समस्याएँ

कुछ मानवीय कारक कृषि की अल्प उत्पादकता के लिए उत्तरदायी थे जो निम्न प्रकार हैं—

- जनसंख्या का अत्यधिक दबाव,
- छोटे कृषकों की उपेक्षा,
- भूमि की गुणवत्ता में कमी,

संस्थागत समस्याएँ

कुछ संस्थागत पहलुओं ने भी उत्पादकता को कम करने में अपनी भूमिका निभाई, जिनमें शामिल प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं—

- दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था का होना।
- अनार्थिक भूमि वितरण।
- विकास नीतियों का अप्रभावी होना।

तकनीकी समस्याएँ—

कृषि उत्पादकता बदलते सम्पर्क में आधुनिक तकनीकों के बिना भी प्रभावित हुई है, जैसे

- उत्पादन की उन्नत तकनीकें।
- उच्च खाद एवं बीजों के प्रयोग का अभाव।
- परम्परागत कृषि यंत्रों का प्रयोग।
- सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा।
- फसलों की सुरक्षा का अभाव।

आर्थिक समस्याएँ

भारतीय किसान गरीबी में जीवनयापन करते हैं, जिससे वे कृषि कार्य को सही ढंग से करने में सक्षम नहीं होते, जिसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता था। जो निम्न प्रकार है

- अपर्याप्त वित्तीय सुविधाएँ।
- दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था।
- पशुओं की घटिया नस्ल।

प्राकृतिक समस्याएँ

भारतीय किसानों को बात प्राकृतिक कारकों का भी सामना करना पड़ता था जो निम्न प्रकार है –

- मानसून पर निर्भरता ।
- प्राकृतिक प्रकोप ।
- भूमिधरण की समस्या ।

भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास –

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार द्वारा कृषि विकास को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रयास किए गए जो निम्न प्रकार हैं

- कृषि योग्य भूमि का विस्तार ।
- सिंचाई सुविधा का विस्तार किया गया
- बाढ़ नियंत्रण ।
- उर्वरकों की उचित व्यवस्था ।
- खाद के प्रयोग एवं प्रचार को बढ़ावा ।
- राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना ।
- कृषि भूमि का विकास ।
- भूमि सुधार कार्यक्रम ।
- कृषि का आधुनिकीकरण ।
- कृषि साख की उचित व्यवस्था ।
- व्यापक फसल बीमा योजना ।
- कृषि विपणन में सुधार नियमित मण्डियों ।
- सहकारी विपणन समितियों ।
- राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ।
- फसल संरक्षण ।
- कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान व महत्व भूतकाल में था, आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा, कृषिगत उत्पादन, ब्रिकी व मूल्यों के संबंध में उचित नीतियों को निर्धारित करने तथा उनका सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करके इस क्षेत्र का है विकास किया जा सकता है ताकि स्थिरता व समानता में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ

1. दत्त एवं सुन्दरम, (2009) भारतीय अर्थव्यवस्था 61 प्रकाशन, सुतम चन्द और सन्स ।
2. प्रकाश, बी.ए., (2009) भारतीय अर्थव्यवस्था 1997– इकोनॉमी रिपोर्ट परफोरमेन्स पर्यासन एजुकेशन ।
3. आर्थिक समीक्षा –2022–23 ।
4. नायूराम का, लक्ष्मीनारायण (2023) भारतीय अर्थव्यवस्था, आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स जयपुर, नई दिल्ली ।
5. राकेश कुमार रोशन और अमित निरंजन सिन्हा (2018), अरिहन्त पब्लिकेशन्स लिमिटेड, मेरठ, यूपी
6. भारत सरकार, योजना आयोग, ग्यारवी पंचवर्षीय योजना ।
7. जैन, एस.जी, विपणन के सिद्धान्त साहित्यभवन, आगरा ।
8. त्रिवेदी, इन्वर्टन एवं जहाना, रेणु विदेशी व्यापार एवं विनियम, राजथान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर ।
9. वान हेबलर, भाट फायड, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त, उ.प्र. संस्थान । हिन्दी समाचार